भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *238

जिसका उत्तर 4 अगस्त, 2021 को दिया जाना है।

13 श्रावण, 1943 (शक)

डिजिटल इंडिया

***238. डॉ. ए. चेल्लाकुमार** :
श्री एम. सेल्वराज :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के अंतर्गत परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) देश और विदेशों की ऐसी कंपनियों की संख्या कितनी है जिन्होंने उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार के साथ करार किया है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितना निवेश किया गया तथा कितने रोजगार सृजित होने की संभावना है;

(घ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान संवितरित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा इस कार्यक्रम में सम्मिलित विभिन्न एजेंसियों के मध्य समन्वय सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ड.): एक विवरण- पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

डिजिटल इंडिया के संबंध दिनांक 4.8.2021 को लोक सभा में
पूछे गए तारांकित प्रश्न सं. *238 के उत्तर में उल्लिखित विवरण-पत्र

(क) : इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारत सरकार ने डिजिटल अभिगम, डिजिटल समावेशन, डिजिटल सशक्तिकरण और डिजिटल विभाजन दूर करने का सुनिश्चिय करके भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि से 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम शुरू किया है। डिजिटल इंडिया ने प्रभावशाली रूप से सरकार और ग्रामीण नागरिकों के बीच की दूरी को काफी कम कर दिया है। इसके अलावा, डिजिटल इंडिया ने नागरिकों को सेवाओं की डिलीवरी और लाभों की प्रत्यक्ष डिलीवरी में सुधार करने में भी मदद की है। देश भर में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एमईआईटीवाई द्वारा की गई कुछ मुख्य पहलों की स्थिति **अनुबंध** में दी गई है।

(ख) : डिजिटल इंडिया एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की कई परियोजनाएं शामिल हैं। डिजिटल इंडिया पहल के तहत उद्योगों (वैश्विक बहुराष्ट्रीय निगमों (एमएनसी) और घरेलू कंपनियों सहित) के साथ कुछ मुख्य संबंध इस प्रकार हैं:

- **प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेशन और उद्यम विकास (टाइड 2.0) योजना** : इस योजना के तहत, उभरती हुई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके आईसीटी स्टार्टअप का समर्थन करने में शामिल इन्क्यूबेटरों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत, 51 इन्क्यूबेशन केंद्रों में 300+ स्टार्टअप शामिल किए गए हैं।

- **एमईआईटीवाई स्टार्ट-अप हब (एमएसएच)** : एमएसएच इन्क्यूबेटरों और स्टार्टअप्स को उनकी दर्जा बढ़ाए जाने की क्षमता, बाजार पहुंच आदि में सुधार करने में सहायता कर रहा है और इसने विभिन्न पणधारकों के साथ भागीदारी भी की है जिसके फलस्वरूप नवोद्भव आधारित आर्थिक निर्माण और प्रौद्योगिकीय उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। एमएसएच के फलस्वरूप 2500 से अधिक स्टार्टअप, 400 इन्क्यूबेटरों, 336 सलाहकारों और 22 अद्यतन तकनीकी जानकारी के उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) का एकीकरण हुआ है।

- **बीपीओ प्रोत्साहन योजना** : बीपीओ प्रोत्साहन योजनाओं के तहत, 179 भारतीय कंपनियों को 255 बीपीओ/आईटीईएस इकाइयों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन (आईपीए) प्राप्त हुआ है।

- **सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम)** : 22+ लाख विक्रेता और सेवा प्रदाता (इनमें से 7 लाख+विक्रेता और सेवा प्रदाता सूक्ष्म और छोटे विक्रेता (एमएसई) हैं)।

- **मेघराज** : पैनल में शामिल 17 निजी क्लाउड सेवा प्रदाता।

- **डिजिलॉकर** : 30 निजी संगठन अनुरोधकर्ता के रूप में।

- **आधार** : 858 सक्रिय नामांकन एजेंसियां।

- **उमंग** : फ्रंटएंड, बैकएंड, हेल्पडेस्क, एआई बॉट, मैप, सर्विस डिलीवरी, पेयू और ऑडिट सेवाओं के लिए 8 कंपनियां।

- **फ्यूचर स्किल्स प्राइम** : नैसकॉम

- **एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस** : 229 बैंक

- **इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण** :

o 14 कंपनियां आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई के तहत पात्र हैं।

o बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना के तहत 5 कंपनियों को अनुमोदित किया गया।

(ग) : अब तक, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं के लिए वित्त वर्ष 2015-16 से 14059.79 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

- संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-सिप्स) के तहत, 83,895 करोड़ रुपए के निवेश और 9,049 करोड़ रुपए के प्रतिबद्ध प्रोत्साहन के साथ 306 इकाइयां अनुमोदित की गई हैं। 1,203.77 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया गया है। अनुमोदित 306 इकाइयों में से 237 इकाइयों ने 26,799 करोड़ रुपए का निवेश किया है और 207 इकाइयों ने उत्पादन शुरू कर दिया है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अब तक 2,52,783 रोजगार सृजित हुए हैं।

- इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) योजना के तहत 3,464 एकड़ के क्षेत्र वाले 19 ग्रीनफील्ड ईएमसी और 3 सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) अनुमोदित किए गए हैं, जिनकी 1,527 करोड़ रुपए के सरकारी सहायता अनुदान सहित कुल परियोजना लागत 3,743 करोड़ रुपए है।

- बीपीओ संवर्धन (आईबीपीएस और एनईबीपीएस) के तहत, 252 बीपीओ/आईटीईएस इकाइयों ने 27 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को शामिल करते हुए 100 से अधिक स्थानों में प्रचालन शुरू किया है, जिससे 42,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है।

(घ) : डिजिटल इंडिया एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की कई परियोजनाएं शामिल हैं। प्रत्येक परियोजना की अपनी बजटीय आवश्यकता होती है और तदनुसार परियोजना की कार्यान्वयन योजना कार्यान्वयन मंत्रालयों/विभागों द्वारा तैयार की गई है और संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा बजट के ब्यौरे बनाए रखे जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया के तहत विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं के लिए वित्त वर्ष 2020-21 में 31 मार्च, 2021 तक 3030.54 करोड़ रुपए का खर्च किया है।

(ङ.) : इस कार्यक्रम में शामिल विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

- डिजिटल इंडिया के तहत विभिन्न पहलों की कड़ी निगरानी।
- तालमेल और सहयोग करने के लिए अंतर-मंत्रालयी बैठकें।
- राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के साथ विशेष रूप से राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के आईटी विभागों के साथ नियमित बैठकें और कार्यशालाएं।
- उद्योगों के साथ नियमित बैठकें और कार्यशालाएं।

*****

अनुबंध

दिनांक 4.8.2021 को लोक सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न सं. *238 के उत्तर में भाग (क) में संदर्भित अनुबंध

पूरे देश में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एमईआईटीवाई द्वारा शुरू की गई कुछ प्रमुख पहलों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:

• **आधार:** आधार 12 अंकों की बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी आधारित पहचान प्रदान करता है जो अद्वितीय, आजीवन, ऑनलाइन और प्रामाणिक है। इसके अलावा, आधार को वैधानिक समर्थन देने के लिए, 'आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016' को 26 मार्च 2016 को अधिसूचित किया गया था। 129.90+ करोड़ से अधिक निवासियों को नामांकित किया गया है।

• **सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी):** सामान्य सेवा केंद्र परियोजना का उद्देश्य विभिन्न सरकार को नागरिकों (जी2सी) और अन्य नागरिक केंद्रित ई-सेवाओं के वितरण के लिए देश भर में 2.50 लाख ग्राम पंचायतों (जीपी) में कम से कम एक सीएससी स्थापित करना है। यह एक आत्मनिर्भर उद्यमिता मॉडल है जो ग्राम स्तर के उद्यमियों (वीएलई) द्वारा चलाया जाता है। जून, 2021 तक, देश भर में कुल 3,99,675 कार्यात्मक सीएससी, जिनमें से 3,00,955 ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर कार्यरत हैं।

• **डिजिटल लॉकर:** डिजिटल लॉकर जारीकर्ताओं के लिए डिजिटल रिपॉजिटरी में दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए रिपॉजिटरी और गेटवे के संग्रह के साथ एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है। डिजिलॉकर के अब तक 7.34 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता। 432 करोड़ प्रामाणिक दस्तावेज जारी किए गए हैं। 1227 जारीकर्ता और 171 अनुरोधकर्ता संगठनों को शामिल किया गया है।

• **नए जमाने के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन (उमंग):**उमंग को प्रमुख सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए एकल मोबाइल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। वर्तमान में, उमंग पर बीबीपीएस उपयोगिता सेवाओं की 20,280 सेवाओं के साथ-साथ केंद्र/राज्य सरकार के 257 विभागों/32 राज्यों की एजेंसियों की 1,251 सेवाओं को शामिल किया गया है।

• **ई-साइन**: ई-साइन सेवा नागरिकों द्वारा कानूनी रूप से स्वीकार्य रूप में ऑनलाइन फॉर्म/दस्तावेजों पर तत्काल हस्ताक्षर करने की सुविधा प्रदान करती है। यूआईडीएआई की ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण सेवाओं का उपयोग करते हुए विभिन्न अनुप्रयोगों द्वारा सेवाओं का लाभ उठाया जा रहा है। जारी किए गए कुल ई-साइन 17.9 करोड़ हैं और सी-डैक द्वारा जारी किए गए 3.16 करोड़ से अधिक ई-साइन हैं।

•**माइगव** : माइगव भारत में सहभागी शासन के लिए अपनी तरह का पहला नागरिक जुड़ाव मंच है। माइगव का उद्देश्य नागरिकों और सरकार के बीच संवाद को सुविधाजनक बनाना, नागरिकों को सरकार के करीब लाना और सरकार को इस मंच के माध्यम से नागरिकों के करीब लाना है। वर्तमान में, 1.85 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता माइगव के साथ पंजीकृत हैं, माइगव प्लेटफॉर्म पर आयोजित विभिन्न गतिविधियों में भाग ले रहे हैं।

• **डिजिटल विलेज:** एमईआईटीवाई ने अक्टूबर, 2018 में 'डिजिटल विलेज पायलट प्रोजेक्ट' भी शुरू किया है। इस परियोजना के तहत 700 ग्राम पंचायतों (जीपी)/गांवों में कम से कम एक ग्राम पंचायत/प्रति जिला प्रति राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं। पेशकश की जा रही डिजिटल सेवाओं डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवा, वित्तीय सेवाएं, कौशल विकास, सौर पैनल संचालित स्ट्रीट लाइट सहित विभिन्न सरकार से नागरिक सेवाएं (जी 2 सी), व्यवसाय से नागरिक (बी 2 सी) सेवाएं हैं।

• **ई-डिस्ट्रिक्ट एमएमपी का राष्ट्रीय रोलआउट:** ई-डिस्ट्रिक्ट एक मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) है जिसका उद्देश्य जिला या उप-जिला स्तर पर पहचान की गई उच्च मात्रा में नागरिक केंद्रित सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी करना है। 28 राज्यों/ 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 709 जिलों में कुल 3,916 ई-जिला सेवाएं शुरू की गई हैं।

• **ओपन सरकार डेटा प्लेटफ़ॉर्म:** ओपन गवर्नमेंट डेटा (ओजीडी) प्लेटफ़ॉर्म भारत सरकार की ओपन डेटा पहल का समर्थन करने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म है। यह सरकार के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने का इरादा रखता है और विभिन्न दृष्टिकोणों को देने के लिए सरकारी डेटा के कई और नवीन उपयोगों के लिए रास्ते भी खोलता है। वर्तमान में, 179 मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 10,624 कैटलॉग के तहत 508,548 संसाधन प्रकाशित किए गए हैं।

• **ई-अस्पताल/ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली (ओआरएस):** ई-अस्पताल एप्लीकेशन अस्पतालों के आंतरिक कार्यप्रवाह और प्रक्रियाओं के लिए अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली है। ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली (ओआरएस) के साथ-साथ ई-अस्पताल अनुप्रयोगों को एनआईसी के राष्ट्रीय क्लाउड पर होस्ट किया जाता है। वर्तमान में, 624 अस्पतालों को 20.32 करोड़ से अधिक ई-अस्पताल लेनदेन के साथ ई-हॉस्पिटल पर जोड़ा गया है, और ओआरएस को देश भर के 363 अस्पतालों द्वारा अपनाया गया है, जिसमें ओआरएस से 40.70 लाख से अधिक अप्वाइंटमेंट बुक किए गए हैं।

• **जीवन प्रमाण:** जीवन प्रमाण के रूप में जानी जाने वाली पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र योजना में जीवन प्रमाण पत्र हासिल करने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की परिकल्पना की गई है। इस पहल के साथ, पेंशनभोगी को संवितरण एजेंसी या प्रमाणन प्राधिकरण के सामने खुद को शारीरिक रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। 2014 से अब तक 4.57 करोड़ से अधिक डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र संसाधित किए जा चुके हैं।

• **एनसीओजी-जीआईएस अनुप्रयोग:** राष्ट्रीय भू-सूचना विज्ञान केंद्र (एनसीओजी) परियोजना, विभागों के लिए साझाकरण, सहयोग, स्थान आधारित विश्लेषण और निर्णय समर्थन प्रणाली के लिए विकसित एक जीआईएस मंच है। अब तक विभिन्न क्षेत्रों में 598 एप्लीकेशन कार्य कर रहे हैं।

• **राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क:** एनकेएन का उद्देश्य देश भर के सभी ज्ञान संस्थानों को उच्च गति डेटा संचार नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना है ताकि संसाधनों और सहयोगी अनुसंधान को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। उच्च शिक्षा और अनुसंधान के संस्थानों को आपस में जोड़ने के लिए एक उच्च गति डेटा संचार नेटवर्क स्थापित किया गया है। अब तक संस्थानों के 1746 लिंक चालू किए जा चुके हैं और उन्हें चालू कर दिया गया है। 517 एनकेएन लिंक पूरे भारत में एनआईसी जिला केंद्रों से जुड़े हैं।

• **प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा):** सरकार ने 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रति परिवार एक व्यक्ति) को कवर करके ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता की शुरुआत करने के लिए "प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा)" नामक एक नई योजना को मंजूरी दी है। अब तक 4.20+ करोड़ उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया है और इसमें से 3.10+ करोड़ से अधिक उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया है। यह योजना देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है।

• **एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई):** यूपीआई एक अग्रणी डिजिटल भुगतान मंच है। यह एक ही मोबाइल एप्लिकेशन (किसी भी भाग लेने वाले बैंक के) में कई बैंक खातों को शक्ति प्रदान करता है, कई बैंकिंग सुविधाओं, निर्बाध फंड रूटिंग और मर्चेंट भुगतान को एक हुड में मिलाता है। यह "पीयर टू पीयर" संग्रह

अनुरोध को भी पूरा करता है जिसे शेड्यूल किया जा सकता है और आवश्यकता और सुविधा के अनुसार भुगतान किया जा सकता है। 229 बैंक यूपीआई सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

• **फ्यूचर स्किल्स प्राइम:** एमईआईटीवाई ने नैसकॉम के सहयोग से फ्यूचर स्किल्स प्राइम नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम का उद्देश्य 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में आईटी पेशेवरों के पुन: कौशल/अप-कौशल का उद्देश्य है जिसमें ऑगमेंटेड/वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग/ 3डी प्रिंटिंग, क्लाउड शामिल हैं। कंप्यूटिंग, सामाजिक और मोबाइल, साइबर सुरक्षा और ब्लॉकचेन।

• **राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन (एनएसएम):** राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन को राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) के साथ एक सुपरकंप्यूटिंग ग्रिड बनाने के लिए जोड़कर देश में अनुसंधान क्षमताओं और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। एन एसएम देश भर के शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में सुपरकंप्यूटिंग सुविधाओं का एक ग्रिड स्थापित कर रहा है। मिशन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सी-डैक), पुणे और भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलुरु द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।।

• **साइबर सुरक्षा**: साइबर कानून, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रशासन से संबंधित मामले। 2000 (2000 का 21) (आईटी अधिनियम, 2000) और अन्य आईटी संबंधित कानून" एमईआईटीवाई के दायरे में आते हैं। मूल आईटी अधिनियम, 2000 को प्रशासित करते समय, एमईआईटीवाई के पास बेहतर इंटरनेट शासन, डेटा सुरक्षा, साइबर सुनिश्चित करने की विशिष्ट जिम्मेदारी है। इंटरनेट पर सुरक्षा, गोपनीयता, प्रौद्योगिकी कंपनियों का प्रचार और विनियमन और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना। भारत ने प्रमुख साइबर सुरक्षा मानकों पर दुनिया के दसवें सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में रैंक करने के लिए 37 स्थान ऊपर उठकर 29 जून, 2021 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) द्वारा शुरू किए गए **वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक (जीसीआई) 2020 में शीर्ष 10** में जगह बनाई है। ।

• **बीपीओ प्रोत्साहन योजना**: भारत बीपीओ प्रोत्साहन योजना (आईबीपीएस) और उत्तर पूर्व बीपीओ प्रोत्साहन योजना (एनईबीपीएस) डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत देश भर के छोटे शहरों में बीपीओ/आईटीईएस संचालन स्थापित करके देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए शुरू की गई थी। देश और उत्तर पूर्वी क्षेत्र। बीपीओ प्रोत्साहन योजनाओं का उद्देश्य देश भर में बीपीओ/आईटीईएस संचालन के संबंध में कुल 53,300 सीटों की स्थापना को प्रोत्साहित करना है। कुल मिलाकर, इन योजनाओं के तहत बीपीओ/आईटीईएस संचालन स्थापित करने के लिए पात्र संस्थाओं को 61,208 सीटें आवंटित की गईं।

• इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण

○ संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज (एम-सिप्स): जून 2021 तक, लगभग 83,895 करोड़ रु. के प्रस्तावित निवेश के साथ 306 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं।

○ इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी): ईएमसी योजना के तहत, 1577 करोड़ रुपये की सरकारी सहायता अनुदान सहित 3,898 करोड़ रुपये परियोजना लागत के साथ 3,565 एकड़ क्षेत्र में 20 ग्रीनफील्ड ईएमसी और 3 सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) देश भर के 15 राज्यों में मंजूर किए गए हैं। देश में इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के लिए बुनियादी ढांचे के आधार को और मजबूत करने और इलेक्ट्रॉनिकी मूल्य श्रृंखला को गहरा करने के लिए संशोधित इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना 1 अप्रैल, 2020 को अधिसूचित की गई है।

****